सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशक की प्रामाणिकता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित की जाती है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समाचारपत्रों को विज्ञापन दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) किसी विशिष्ट उदाहरण के अभाव में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

उर्वरक-वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए रेक प्वाइंट का खोला जाना

1672. **श्री सुरेश पचौरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में रेक-प्वाइंट खोलने के क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार उर्वरक वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त रेक प्वाइंट खोलने पर विचार कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसे कितने अतिरिक्त रेक-प्वाइंट खोले जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) अर्थव्यवस्था रेक प्वाइंट खोलने के लिए मूल मानदण्ड को न्यूनतम परिवहन लागत प्रदान करना है। रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार रेक प्वाइंट द्वारा लगभग 100 कि०मी० तक के भीतरी प्रदेश की सेवा प्रदान करनी चाहिए और प्रत्येक रेक प्वाइंट के लिए पर्याप्त उर्वरक का आवागमन होना चाहिए ताकि प्रत्येक सप्ताह दो या अधिक रेक प्राप्त कर सके।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में और रेक संचालन प्वाइंट खोलने के लिए विकास कार्य प्रगति पर है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Stenographers in the Ministry of Personnel

1673. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of Stenographers in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;

(b) whether the quota reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes has been completed;

(c) if not, what steps being taken by Government to complete that quota; and

(d) when the reservation quota is proposed to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) 127.

(b) to (d) Stenographers in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension are borne on a common cadre controlled by the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs appoint and post stenographers to the various cadre units controlled by it including Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions. The prescribed quota of vacancies is kept reserved for candidates belonging to SC/ST by the Cadre Controlling authority as a whole but the posting in the cadre units is not strictly based on quota for the respective units.

उर्वरकों पर राज-सहायता कम किए जाने का उर्वरकों की मांग पर प्रभाव

1674. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों पर राज सहायता को समाप्त कर देने से देश में उर्वरकों की मांग पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान, बंगला देश और इंडोनेशिया द्वारा अपनाई गई कार्य-योजना का अध्ययन कर लिया है, जहां यद्यपि, राज्य सहायता को समाप्त कर दिया गया था तथापि इन देशों ने उर्वरक फैक्टरियों की समस्याओं को इस प्रकार हल किया जिससे कि उर्वरकों की मांग में कोई कमी न आये ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त देशों में उत्पादन लागत को कम बनाये रखने के लिए उर्वरक फैक्टरियों द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए थे और क्या इन उपायों को हमारे देश में अपनाया जा सकता है और यदि नहीं तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) कुछ निम्न विश्लेषण उर्वरकों को छोड़कर, जो अपेक्षाकृत निम्न मात्राओं में बेचे जाते हैं, सरकार ने उर्वरकों पर राज सहायता नहीं हटाई है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

1675. [*Transferred to the 30th July, 1991*]

Parliamentary Committee to review the use of Nuclear Power

1676. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Nuclear power generation is now being viewed world-wide as a deathtrap after the Chernobyl Disaster; and

(b) if so, whether a Parliamentary Committee will be asked to review the entire question of the use of nuclear power including food irradiation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) It is not correct to say that nuclear power is viewed as a death-trap world-wide. The causes of Chernobyl reactor accident in the Soviet Union and its possible health effects have been extensively studied and have been the subject of scientific investgations by such expert bodies as the International Atomic Energy Agency. The Chernobyl Nuclear Reactor design was of a type that is not very common in the rest of the world including India. Lessons learnt from such occurrences are however reviewed in detail and wherever applicable are incorporated in the design parameters and operating practices. As of today 423 nuclear power reactors are in operation and 83 under construction across the world. 19% of electricity production in the world is from nuclear reactors.

(b) The safety of the nuclear power plants is constantly reviewed by the Atomic Energy Regulatory Board along with the experts it has chosen from a wide range of organisations. As such there does not seem to to be any case for a special parliamentary committee.

45 per cent cut in fertilizers subsidy

1677. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention is drawn to the news item published in Hindustan Times on 17th July, 1991 captioned 45 per cent cut likely in fertilizer subsidy, if so, what is Government's reaction thereto;

(b) whether it is also a fact that small and Marginal farmers are not benefited by subsidy, but mainly big farmers could be benefited; and

(c) what is the total quantum of subsidy given by Government?